whole state is Rs. 354 crore to be utilised over a six year period. The objectives of the project are to increase forest productivity and quality, protect the environment and strengthen and improve the functioning of the forestry administration in the State. The implementation of the project will further promote afforestation and tree planting activities, including social forestry, in the state.

Depletion and Destruction of Reserve Forest Land in Andhra Pradesh

2784. DR. YELAMAN CHILI SIVAJI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is large scale depletion and destruction of reserve forest in Andhra Pradesh;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) Following steps are taken to arrest this with details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) No large-scale destruction of reserve forest has been reported in the state of Andhra Pradesh.

(c) following steps are taken to check destruction of forests in Andhra Pradesh:

(i) Forest (conservation) Act, 1980 was enacted to check diversion of forests land for non-forestry purpose.

(ii) 16 Flying Squad Parties, 24 Mobile Parties and Protection Force Teams are engaged to keep vigil on smuggling of forest produce and encroachments on forest land;

(iii) Interior forest areas are connected with wireless network to improve communication. 116 fixed wireless stations and 86 mobile wireless sets have been provided in vulnerable forest areas to detect smuggling of forest produce;

(iv) Field staff is equipped with vehicles in vulnerable areas;

(v) The police help in sought as and when required to apprehend notorious smugglers;

(vi) Village communities are involved in forest protection through the mechanism of usufruct sharing; and

(vii) 100 per cent Central assistance is provided to the Andhra Pradesh Government under 'Modern Fire Control Methods' Scheme to control forest fires.

प्रदूषित महानगर

2785. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है कि देश के चार महानगरों में से कौन सा महानगर सबसे ज्यादा प्रदूषित है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी एवं अनुसंधान संस्थान ने भी इस संदर्भ में कोई अध्ययन किया है ;

(घ) इन महानगरों में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) प्रदूषित वातावरण के कारण इन चार महानगरों के निवासियों में फैलती बीमारियों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्य क्रम के तहत देश में परिवेशी वायु गुणवत्ता के सर्वेक्षण की मानीटरी कर रहा है जिसमें चार महानगर अर्थात दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई शामिल हैं । सर्वेक्षित प्रमुख वायु गुणवत्ता पैरामीटरों में निलंबित धूलकण, नाइट्रोजन डाईआक्साइड और सल्फर डाईआक्साइड शामिल हैं । तथापि, भिन्न-भिन्न प्रदूषण पैरामीटरों के लिए कोई पारस्परिक वैटेज नहीं है जिससे नगरों का प्रदूषण वर्गीकरण किया जा सके ।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला है कि परिवेशी वायु में निलंबित धूलकण के वार्षिक औसत सांद्रण का स्तर दिल्ली में अधिकतम है ।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान दस प्रमुख शहरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर और कोचीन में इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वायु गुणवत्ता मानीटरी स्टेशनों का एक नेटवर्क संचालित कर रहा है ।

(घ) उठाये गये कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:-

(1) प्रदूषक उद्योगों का प्रमुख श्रेणियों के लिये बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये हैं ।

(2) उद्योगों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिये गये हैं तथा चूककर्ताओं के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाती है ।

(3) वाहनों से प्रदूषण के नियंत्रण के लिये केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों हेतु उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं ।

(4) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत वाहन उत्सर्जन हेतु अधिक सख्त मानक अधिसूचित किये गये हैं जो अप्रैल, 1996 से प्रभावी होंगे ।

(5) आटोमोबाइल विनिर्माताओं से कहा गया है कि वे अपनी प्रौद्योगिकी का विकास और उसमें सुधार करें ताकि वाहनों के उत्सर्जनों के लिए सख्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

(6) प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु कई जनजागरूकता अभियान चलाये गये हैं ।

(ङ) किसी भी महानगर में प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में कोई व्यापक महानगरीय अध्ययन नहीं किए गए हैं । तथापि, महानगरों के कम आय वाले, गन्दी जगहों में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में नासिका सम्बंधी बीमारी श्वसनी-शोथ जैसी श्वसन तंत्रो बीमारियां अधिक देखी गई है । ऐसी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों और प्रदूषण के बीच निर्णायक रूप में कोई संबंध प्रमाणित नहीं किया जा सका है ।

'Percentage of forest cover in Andhra Pradesh'

2786. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the percentage of forest cover in Andhra Pradesh;

(b) what is the desired percentage;

(c) whether it is as per schedule; and

(d) what steps are taken to reach the recommended scale with details thereof?